Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 4, July-2021, ISSN 2230-7540

महाविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं पर एक अध्ययन

Ajeet Kumar Sahu[1]*, Dr. Pradeep Kumar Dubey[2]

[1] Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

[2] Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

सार - *स्वतंत्रता के बाद पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं की अवधि में, भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के साथ-साथ पुस्तकालयों के विकास के लिए आयोगों और शिक्षा नीतियों की भी स्थापना की। भारत सरकार ने मई 1986 में एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नीति ने मौजूदा पुस्तकालयों का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया और नए पुस्तकालयों की स्थापना की। उच्च शिक्षा प्रणाली परोक्ष रूप से मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा नियंत्रित है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रत्येक सहपाठी के पास एक योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष होना चाहिए। पुस्तकालय के विकास के लिए बुक लिफ्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर और चपरासी भी आवश्यक हैं। उच्च शिक्षा के हर महाविद्यालय में लाइब्रेरी ऑटोमेशन की जरूरत है।*

कीवर्ड - *महाविद्यालय, पुस्तकालय, प्रणाली, सेवा।*

----------X----------

परिचय

विश्व में भारत एक विशाल शिक्षा प्रणाली है, भारतीय शिक्षा प्रणाली ने अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में एक मजबूत स्थिति पर विजय प्राप्त की है। भारत आज विदेशी छात्रों के बीच उच्च शिक्षा के लिए एक विश्व केंद्र के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि देश में विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक पाठ्यक्रम हैं। भारतीय उद्यमी पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं। भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा शामिल है।[1] प्रारंभिक शिक्षा में आठ साल की शिक्षा शामिल है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा में से प्रत्येक में दो साल की शिक्षा होती है। उच्च शिक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा या 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शुरू होती है। स्ट्रीम के आधार पर भारत में ग्रेजुएशन करने में तीन से पांच साल लग सकते हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सामान्यतः दो से तीन वर्ष की अवधि का होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शोध करने की गुंजाइश भी खुली रहती है। भारत में तकनीकी शिक्षा समग्र शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा योगदान देती है और हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली

1830 के दशक में मूल रूप से लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा सहित आधुनिक स्कूल प्रणाली भारत में लाई गई थी। पाठ्यक्रम आधुनिक विषय जैसे विज्ञान और गणित तक ही सीमित था, और तत्वमीमांसा और दर्शन जैसे विषयों को अनावश्यक माना जाता था। शिक्षण कक्षाओं तक ही सीमित था और शिक्षक और छात्र के बीच घनिष्ठ संबंध के रूप में प्रकृति के साथ संबंध टूट गया था। उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड वर्ष 1921 में भारत में स्थापित पहला बोर्ड था। 1952 में, बोर्ड के संविधान में संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कर दिया गया। दिल्ली के सभी स्कूल और कुछ अन्य क्षेत्र बोर्ड के अधीन आ गए।[2]

भारतीय शिक्षा प्रणाली की श्रेणियां

www.ignited.in

भारत का संविधान 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। 14-18 आयु वर्ग के सभी युवाओं को अच्छी गुणवत्ता, उपलब्ध, सुलभ और सस्ती माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना। उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन और विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा संप्रदाय या के बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। उच्च शिक्षा केंद्र और राज्यों दोनों की साझा जिम्मेदारी है।

उच्च माध्यमिक परीक्षा (ग्रेड 12 परीक्षा) उत्तीर्ण करने के बाद छात्र सामान्य डिग्री कार्यक्रमों जैसे कला, वाणिज्य या विज्ञान में स्नातक की डिग्री या इंजीनियरिंग, कानून या चिकित्सा जैसे पेशेवर डिग्री कार्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा का शासी निकाय है।

भारत में उच्च शिक्षा

आजादी के बाद सरकार द्वारा ली गई शिक्षा की जिम्मेदारी, वे अपने देश और इसकी अनमोल विरासत के लिए महसूस करते हैं। राधा कृष्णन आयोग के सुझावों पर स्वतंत्रता के तुरंत बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना दिसंबर 1953 में (नवंबर 1956 में एक वैधानिक निकाय के रूप में) न केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बल्कि गुणवत्ता बनाए रखने और इसके सर्वांगीण विकास को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) और शिक्षा आयोग (1964-66) भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर भविष्य की कार्रवाई के सुझाव के लिए नियुक्त किए गए थे।[3]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई) को मई 1986 में संसद द्वारा अपनाया गया था। एनपीई की समीक्षा करने और इसके संशोधनों के लिए सिफारिशें करने के लिए मई 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। एनपीई की मुख्य कुंजी इस प्रकार हैं:-

- शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है।
- विषमताओं को दूर करना और शैक्षिक अवसरों को समान बनाना।
- महिला सशक्तिकरण में भूमिका को बढ़ावा देना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा प्रदान करना।
- अल्पसंख्यक समूहों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना जो शैक्षिक रूप से वंचित हैं।
- शारीरिक रूप से विकलांग और वयस्क शिक्षा के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

आरयूएसए को 2013 में लॉन्च किया गया था और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य पात्र उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त पोषण (सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 65:35 के अनुपात में और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में) मानदंड आधारित और बाहर आने पर निर्भर होगा। पहचान किए गए संस्थानों तक पहुंचने से पहले राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालय से राज्य उच्च शिक्षा परिषदों को धन का प्रवाह होगा। राज्यों को वित्त पोषण राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रत्येक राज्य की रणनीति का वर्णन करेगा।[4] आरयूएसए को राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण, परियोजना अनुमोदन बोर्ड और केंद्र में राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय और राज्य स्तर पर राज्य उच्च शिक्षा परिषद और राज्य परियोजना निदेशालय सहित संस्थागत संरचना के माध्यम से कार्यान्वित और निगरानी की जाती है। रूसा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के रूप में मान्यता को अपनाना।
- संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में खुद को अनुसंधान और नवाचारों के लिए समर्पित करने के लिए एक सक्षम माहौल बनाना।
- नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता सृजित करके और नए संस्थानों की स्थापना करके संस्थागत आधार का विस्तार करना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा के पर्याप्त

www.ignited.in

अवसर प्रदान करके उच्च शिक्षा में समानता में सुधार करना; महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के समावेश को बढ़ावा देना।

भारत में पुस्तकालय विज्ञान का इतिहास

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने श्री के.पी. सिन्हा भविष्य की पुस्तकालय संरचना और भारत में इसके विकास की सिफारिश करेंगे। समिति ने 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1959 में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मुख्य रूप से सार्वजनिक पुस्तकालयाध्यक्षों को निर्देश देने और शिक्षण सहायक सामग्री और सामग्री तैयार करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय विज्ञान संस्थान स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान किया। 1985 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, दोनों ने पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति पर अलग-अलग प्रारूप तैयार किए। इसने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा।

यूजीसी ने अपनी विभिन्न समितियों और विषय पैनलों के माध्यम से स्वतंत्रता भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों पुस्तकालयों के कामकाज और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए, यूजीसी ने डॉ. एस.आर. 1959 में रंगनाथन।

महाविद्यालयों में पुस्तकालयों की भूमिका

आज के पुस्तकालयों ने आधुनिक समाज में एक नई भूमिका ग्रहण की है, जिसके द्वारा वे शैक्षिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और नए मीडिया को एकीकृत करते हैं। सूचना युग में अकादमिक पुस्तकालयों/पुस्तकालयाध्यक्षों की भूमिका उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त और सटीक जानकारी तक पहुंच को बढ़ावा देना है। इंटरनेट अद्भुत चीज है लेकिन यह पुस्तकालय परिसर का विकल्प नहीं है।[5] पुस्तकालयाध्यक्ष छात्रों और अन्य उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं और सिखाते हैं कि सूचना के सर्वोत्तम स्रोतों को कैसे खोजा जाए, चाहे वह प्रिंट हो या ऑनलाइन। कुछ साल पहले पुस्तकालय पुस्तक केंद्रित संस्थान थे। वे सिर्फ प्रिंट कार्ड कैटलॉग थे। पुस्तकालयों को हम ज्ञान/सूचना के भंडार गृह के रूप में जाना जाता है, लेकिन आजकल पुस्तकालयों की अवधारणा को बदल दिया गया है।

साहित्य की समीक्षा

कौर, हरजिंदर। (2015)[6] अनुसंधान और शिक्षण के लिए संसाधनों के उपयोग के विशिष्ट संदर्भ के साथ, जिम्बाब्वे और ज़ुलुलैंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षाविदों और पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा इंटरनेट के उपयोग, रुझानों की जांच करें। अध्ययन आबादी के बीच एक प्रश्नावली के माध्यम से एक सर्वेक्षण के परिणाम दोनों संस्थानों के पुस्तकालयाध्यक्षों के बीच उच्च कंप्यूटर और इंटरनेट कौशल का संकेत देते हैं। परिणाम यह भी इंगित करते हैं कि ई-मेल और वेब का उपयोग कार्य और व्यक्तिगत उपयोग के लिए सबसे अधिक किया जाता था, जबकि टेलनेट, अन्य पुस्तकालय ओपेक और इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं का उपयोग कार्य उद्देश्य के लिए सबसे अधिक किया जाता था।

मुगविसी, टी., ओचोला, डी.एन. (2012)[7] इंटरनेट और आईटी कौशल का वर्णन करते हैं जो सूचना पेशेवरों द्वारा यूके में उच्च शिक्षा क्षेत्र के बदलते संदर्भ में शिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान के लिए उनके समर्थन में आवश्यक हैं और प्रबंधन के विकास (या आभासी) सीखने का वातावरण। लेखक इस बात पर जोर देता है कि आईटी कौशल, विशेष रूप से इंटरनेट के संबंध में, आवश्यक हैं, कुछ अधिक बुनियादी कौशल जो सूचना पेशेवर के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

अर्जुन, के. (2012)[8] उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में स्वचालन की स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण के परिणाम प्रस्तुत करें। छह विश्वविद्यालयों के केंद्रीय पुस्तकालयों के प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष से डेटा प्राप्त करने के लिए एक संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। सर्वेक्षण में मुख्य रूप से पुस्तकालय स्वचालन के विभिन्न पहलुओं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे, आंतरिक गतिविधियों, सूचना सेवाओं और उनके उपयोग, जनशक्ति विकास और बजट को शामिल किया गया है। यह अध्ययन विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की गतिविधियों के स्वचालन को समर्थन देने में इनफ्लिबनेट केंद्र की भूमिका से भी संबंधित है।

कुमार, पी.एस.जी. (2011)[9] आईसीटी बुनियादी ढांचे, पुस्तकालय स्वचालन की स्थिति, पुस्तकालय स्वचालन के कार्यान्वयन में बाधाओं और आईसीटी के उपयोग के प्रति पुस्तकालय के दृष्टिकोण का विश्लेषण करके कानपुर,

भारत में 31 महाविद्यालयों पुस्तकालयों में पुस्तकालय सॉफ्टवेयर (एलएस) और सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग का निरीक्षण करें। चयनित महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों के साथ प्रश्नावली, अवलोकन और अनौपचारिक साक्षात्कार का उपयोग करके किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि पुस्तकालय गतिविधियों को स्वचालित नहीं करने के लिए बजट की कमी, जनशक्ति की कमी, कुशल कर्मचारियों की कमी और प्रशिक्षण की कमी मुख्य बाधाएं हैं।

बिडिस्कोम्बे, आर। (2011)[10] "दक्षिण भारत में मत्स्य महाविद्यालय पुस्तकालयों में इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं का मूल्यांकन: एक अध्ययन" शीर्षक वाले पत्र में चार मत्स्य महाविद्यालय पुस्तकालयों में इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं का वर्णन किया गया है। लेखकों ने पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की।

कृष्ण कुमार और शर्मा, जयदीप, (2010)[11] आगरा के तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय पेशेवरों के सूचना साक्षरता कौशल का अध्ययन करते हैं। संरचित प्रश्नावली और साक्षात्कार का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि अधिकांश पुस्तकालय पेशेवर कंप्यूटर साक्षर हैं, जिनके पास पीजीडीसीए, डीसीए और अन्य अल्पकालिक पाठ्यक्रम जैसे कंप्यूटर पाठ्यक्रम हैं। वे ई-संसाधनों के उपयोग, वेब संसाधनों के मूल्यांकन, आईपीआर, वेब ओपेक, सर्च इंजन आदि के बारे में भी जानते हैं। लेखक अनुशंसा करते हैं कि पुस्तकालय पेशेवरों को सूचना प्रौद्योगिकी की विभिन्न उन्नत अवधारणाओं पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सुकु, जे., पिल्लै, एम.जी. (2010)[12] दिल्ली के आईसीएआर संस्थानों और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में कार्यरत शिक्षकों और शोध वैज्ञानिकों के व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। अध्ययन का शीर्षक था "भारत में आईसीएआर संस्थानों में काम कर रहे कृषि वैज्ञानिकों की सूचना तलाशने की रणनीतियाँ"। परिणाम से पता चला कि कृषि वैज्ञानिकों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुस्तकालय और सूचना केंद्र सबसे पसंदीदा स्रोत थे। उपयोगकर्ता कम्प्यूटरीकृत सूचना खोज सुविधा पर बहुत अधिक निर्भर थे।

जोशी, मनोज के. (2010)[13] बोत्सवाना में शिक्षा के महाविद्यालय में संग्रह विकास नीतियों की उपलब्धता और उपयोग पर चर्चा की। अधिकांश पुस्तकालयों में संग्रह विकास नीतियां नहीं थीं। आगे यह पाया गया कि अधिकांश पुस्तकालयों ने नीतियों के निर्माण में अपने उपयोगकर्ताओं को शामिल नहीं किया और संग्रह विकास के लिए इन्हें लागू नहीं किया।

कृष्ण कुमार, और शर्मा, जयदीप, (2009)[14] "अजमल खान तिब्बिया महाविद्यालयों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों के सूचना चाहने वाले व्यवहार" नाम के तहत महाविद्यालयों के छात्रों के व्यवहार की जानकारी की जांच करने के लिए एक अध्ययन किया; एक सर्वेक्षण।" 60 विद्यार्थियों से प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़े एकत्रित किए गए। 51.67% उपयोगकर्ता प्रतिदिन पुस्तकालयों का दौरा कर रहे थे। समाचार पत्र सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज थे जिसके बाद पुस्तकों और पत्रिकाओं का उपयोग किया जाता था। सूचना प्राप्त करने के लिए वाहक विकास सबसे पसंदीदा प्रतिक्रिया थी। नब्बे प्रतिशत छात्र इस बात से सहमत थे कि छात्रों को सूचना स्रोतों और सेवाओं के प्रभावी और कुशल उपयोग के लिए अपने विषय क्षेत्र में सूचना स्रोत का उपयोग करने के निर्देश की आवश्यकता है।

नतनबिगा, सी.एम. (2009)[15] ने नाइजीरिया में शिक्षा के महाविद्यालय में "नाइजीरिया में शिक्षा के महाविद्यालय में लागू पुस्तकालय सेवा मानकों" के तहत पुस्तकालय सेवा मानकों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए एक अध्ययन किया। संरचित प्रश्नावली के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया था। अध्ययन के परिणामों से पता चला कि महाविद्यालयों शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुशंसित पुस्तकालय बुनियादी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। ये अनुक्रमण और सारकरण सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे थे।

अध्ययन के उद्देश्य

- पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रणाली और सेवाओं के बारे में जानना।
- पुस्तकालय में नवीनतम प्रौद्योगिकी के लाभों के बारे में जानना।
- पुस्तकालय के संग्रह विकास के बारे में जानना।

अनुसंधान क्रियाविधि

अनुसंधान पद्धति वैज्ञानिक और वैध बनाने के लिए अन्वेषक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की समग्रता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी शोध की सफलता

www.ignited.in

अपनाई गई पद्धति और डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए नियोजित उपायों और तकनीक पर निर्भर करती है। कार्यप्रणाली एक शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का तरीका है। इसे वैज्ञानिक रूप से शोध कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन करने के विज्ञान के रूप में समझा जा सकता है। "वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा शोधकर्ता घटनाओं का वर्णन, व्याख्या और भविष्यवाणी करने के अपने काम के बारे में जाते हैं, उन्हें शोध पद्धति कहा जाता है।" आमतौर पर पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में लागू अनुसंधान विधियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ऐतिहासिक तरीका

ऐतिहासिक पद्धति में वे तकनीकें और दिशानिर्देश शामिल हैं जिनके द्वारा इतिहासकार अनुसंधान के लिए प्राथमिक स्रोतों और पुरातत्व के अन्य साक्ष्यों का उपयोग करते हैं और फिर पोस्ट के खाते के रूप में इतिहास लिखते हैं। "अध्ययन या पेशे के चुने हुए क्षेत्र की पृष्ठभूमि और विकास को सीखने और समझने की प्रक्रिया और संगठनात्मक संस्कृति वर्तमान प्रवृत्तियों और भविष्य की संभावनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।"

सर्वेक्षण विधि

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्वेक्षण अनुसंधान का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। यह मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में मामलों की वर्तमान स्थिति से संबंधित डेटा के संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुति से संबंधित है। सर्वेक्षण विधि व्यक्तिगत साक्षात्कार, डाक प्रश्नावली, टेलीफोन, व्यक्तिगत चर्चा, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण आदि के माध्यम से संपर्क किया जाता है।

केस स्टडी विधि

केस स्टडी एक जनसंख्या प्रकार का गुणात्मक शोध है और इसे "एक अलग प्रविष्टि (जो एकल सेटिंग विषय, संग्रह या घटना हो सकती है) की गहराई से जांच के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इस धारणा पर कि व्यापक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करना संभव है किसी विशिष्ट उदाहरण या मामले की गहन जाँच।"

डेल्फी विधि

डेल्फी पद्धति मूल रूप से किसी समस्या पर विशेषज्ञ की राय के बीच आम सहमति प्राप्त करने की एक तकनीक है। अनुसंधान के उद्देश्यों और उद्देश्यों को स्थानांतरित करते हुए एक प्रश्नावली तैयार की जाती है। पहचान की गई समस्या को कई दौर में विशेषज्ञों के पैनल के सामने रखा जाता है, जब तक कि आम सहमति नहीं बन जाती।

सांख्यिकीय विधि

इस शोध में एकत्रित आंकड़ों को सांख्यिकी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, शोधकर्ता वर्णनात्मक रूप में डेटा एकत्र करते हैं और फिर इसे सांख्यिकीय रूप में स्थानांतरित करते हैं। सांख्यिकीय विधियाँ गणितीय तकनीकें हैं जिनका उपयोग संख्यात्मक डेटा की व्याख्या को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। सांख्यिकीय पद्धति को प्रमुख उद्देश्य के अनुसार तकनीकों के चार सेटों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

नमूने का चयन

इस अध्ययन के दायरे में 50 सरकारी महाविद्यालय हैं और इनसे जुड़े पुस्तकालय जांच का विषय हैं। सभी महाविद्यालय बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध हैं।

तालिका 1: **प्रश्नावली- वितरित और उत्तर**

महाविद्यालय की संख्या	वितरित		जवाब दिया	
	पुस्तकालयाध्यक्ष	संकाय सदस्य	पुस्तकालयाध्यक्ष	संकाय सदस्य
50	50	280	50	230

कार्यप्रणाली लागू

इस शोध में एक उपकरण के रूप में अध्ययन के लिए एक अच्छी तरह से संरचित प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है। भोपाल संभाग के पुस्तकालय और उनके ग्राहक (संकाय सदस्य) का एक नमूना है। दो श्रृंखलाओं में प्रश्नावली को टी ओ प्रशासित किया गया था।

डेटा विश्लेषण

वर्तमान अध्याय शोधकर्ता द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली के माध्यम से व्यवस्थित रूप से एकत्र किए गए डेटा के सारणीकरण और विश्लेषण से संबंधित है।

www.ignited.in

पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं के संबंध में पुस्तकालय मूल्यांकन

तालिका 2: महाविद्यालय के उत्तरदाता

क्रम संख्या	जिला	प्रश्नावली वितरित	प्रश्नावली उत्तरदाता	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1	भोपाल	12	12	100%
2	रायसेन	09	09	100%
3	राजगढ़	07	07	100%
4	सीहोर	12	12	100%
5	विदिशा	10	10	100%
	कुल	50	50	100%

तालिका चयनित क्षेत्र के बारे में जानकारी दर्शाती है। पूरे 5 जिले 100% दिखाते हैं। यह देखा गया है कि पुस्तकालयाध्यक्ष अपने संस्थान में बहुत व्यस्त हैं लेकिन सर्वेक्षण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पूरी रुचि दिखाते हैं। यह भी देखा गया है कि 24% महाविद्यालय भोपाल और सीहोर जिले में हैं, इसके बाद विदिशा जिले में 20% महाविद्यालय हैं, 18% महाविद्यालय रायसेन जिले में हैं और 14% महाविद्यालय राजगढ़ जिले में हैं। राजगढ़ जिले की तुलना में भोपाल और सीहोर जिले में अधिक महाविद्यालय हैं।

तालिका 3: पुस्तकालय प्रणाली

क्रम संख्या	जिला	महाविद्यालय प्रत्युत्तर	पुस्तकालय प्रणाली	
			ओपन एक्सेस सिस्टम	क्लोज एक्सेस सिस्टम
1	भोपाल	12	09	03
2	रायसेन	09	05	04
3	राजगढ़	07	-	07
4	सीहोर	12	08	04
5	विदिशा	10	05	05
	कुल	50	27	23

तालिका चयनित क्षेत्र में पुस्तकालय प्रणाली के बारे में जानकारी दर्शाती है। 54% महाविद्यालय लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस सिस्टम है शेष 46% महाविद्यालय लाइब्रेरी में क्लोज एक्सेस सिस्टम है। ओपन एक्सेस सिस्टम में उपयोगकर्ता बुक शेल्फ के पास पहुंचते हैं और वांछित सामग्री चुनते हैं लेकिन क्लोज एक्सेस सिस्टम में उपयोगकर्ता बुक शेल्फ तक नहीं पहुंच सकते हैं।

तालिका 4: पुस्तकालय स्वचालन

क्रम संख्या	जिला	महाविद्यालयों की संख्या	स्वचालन	
			हां	नहीं
1	भोपाल	12	12	–
2	रायसेन	09	02	07
3	राजगढ़	07	02	05
4	सीहोर	12	03	09
5	विदिशा	10	02	08
	कुल	50	21	29

तालिका चयनित क्षेत्र में पुस्तकालय स्वचालन के बारे में जानकारी दर्शाती है। 42% पुस्तकालयों में स्वचालन की सुविधा है और 58% पुस्तकालयों में स्वचालन की कोई सुविधा नहीं है। यह देखा गया है कि भोपाल जिले के 100% पुस्तकालयों के बाद राजगढ़ जिले के 28.57% पुस्तकालयों, सीहोर जिले के 25% पुस्तकालयों, रायसेन जिले के 22.2% पुस्तकालयों और विदिशा जिले के 20% पुस्तकालयों में स्वचालन की सुविधा है।

निष्कर्ष

पुस्तकालय की मूल अवधारणा उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित है। पुस्तकालय अपने कार्यक्रमों की योजना पुस्तकालय विज्ञान के पंचांगों के दिशा-निर्देशों पर आधारित करता है। पुस्तकालयों को सूक्ष्म दस्तावेज़ों से मैक्रो दस्तावेज़ों में स्थानांतरित कर दिया गया है। लाइब्रेरियन का अधिकतम पद स्थायी लाइब्रेरियन से भरा नहीं है। पुस्तकालयाध्यक्षों को वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में पुस्तकालय सेवाओं में सुधार के लिए उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता और मांग के अनुसार रणनीतियों को नया स्वरूप देना चाहिए। उपयोगकर्ता अध्ययन ने व्यक्त किया कि ज्ञान के विकास के लिए कंप्यूटर, पुस्तकों और पत्रिकाओं की पहुंच आवश्यक है। अपने क्षेत्र में वर्तमान विकास को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय स्वचालन भी आवश्यक है।

संदर्भ

1. बिरदार, बी.एस., कुमार, पी. धरानी, महेश, वाई। (2009)। लाइब्रेरी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस

www.ignited.in

महाविद्यालयों, शिमोगा, ए केस स्टडी: एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, वॉल्यूम 56 में सूचना स्रोतों और सेवाओं का उपयोग। नंबर 2, पीपी 63-68।

2. पांडे, एस.के.शर्मा, (2007)। पुस्तकालय और समाज। दिल्ली: ग्रंथ अकादमी।
3. अहमद, मोइन, हरिदासन, सुधारा (2006)। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान पुस्तकालय में विद्वानों द्वारा पत्रिकाओं का उपयोग; एक उपयोगकर्ता का सर्वेक्षण ", आईएएसएलआईसी बुलेटिन, वॉल्यूम। 51, (2), पीपी। 05 -17।
4. अरोड़ा, जगदीश। (2004) एक पारंपरिक पुस्तकालय को एक संकर पुस्तकालय में बदलना: केंद्रीय पुस्तकालय में नेतृत्व और प्रबंधन कौशल का उपयोग। आईआईटी दिल्ली। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुस्तकालय, 22(2-3):पी.5-15।
5. पटेल, जशु कृष्ण कुमार, (2001)। भारत में पुस्तकालय और पुस्तकालय। लंदन: ग्रीन वुड प्रेस .P.80.
6. कौर, हरजिंदर। (2015)। पंजाब के लॉ महाविद्यालयों पुस्तकालय। भारतीय पुस्तकालय संघ के जर्नल। 51(3) .पी.31-39।
7. मुग्विसी, टी., ओचोला, डी.एन. (2012), ज़िम्बाब्वे विश्वविद्यालय और ज़ुलुलैंड में अकादमिक लाइब्रेरियन के बीच इंटरनेट का उपयोग। लिबरी, 53 (3), पी.194-201।
8. अर्जुन, के. (2012)। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के विभागीय पुस्तकालयों का उपयोग: एक अध्ययन, लैप लैम्पर्ट, अकादमिक प्रकाशन।
9. कुमार, पी.एस.जी. (2011)। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का एक छात्र मैनुअल। 2 वॉल्यूम। दिल्ली: बी.आर. प्रकाशन निगम, पी. 561-571
10. बिडिस्कोम्बे, आर. (2011)। सूचना पेशेवरों का विकास, इंटरनेट और आईटी कौशल की जरूरतें: बर्मिंघम विश्वविद्यालय में अनुभव। कार्यक्रम, 35 (2), 157-166।
11. कृष्ण कुमार और शर्मा, जयदीप, (2010) भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी के डेसीडॉक जर्नल 30 (5)। पी 3 -8।
12. सुकु, जे., पिल्लै, एम.जी. (2010)। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के स्वचालन पर परिप्रेक्ष्य; स्थिति की समस्याएं और संभावनाएं। जर्नल ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरियनशिप, 31 (2), पी.151 -159।
13. जोशी, मनोज के. (2010)। भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा: कुछ सरकारी पहल, पुस्तकालय और सूचना प्रौद्योगिकी के डेसीडॉक जर्नल, 30(5)। पी. 67-73.
14. कृष्ण कुमार, और शर्मा, जयदीप, (2009)। भारत में पुस्तकालय और सूचना शिक्षा, नई दिल्ली: हर-आनंद, पी-72।
15. नतनबिगा, सी.एम. (2009), इंफॉर्मेशन स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन इंडियन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कार्यक्रम, 38 (4)। पी.232-239।

Corresponding Author

Ajeet Kumar Sahu*

Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.